**राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ**

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 46/2002

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल कार्यालय, रेजीडेंसी रोड, गोयल अस्पताल के पास, जोधपुर।

**----अपीलार्थी**

**बनाम**

1. श्री सूरज करण @ सूरजमल बी/सी माली की विधवा श्रीमती साम्या।
2. सिन्टी पुत्र श्री सूरज करण @ सूरजमल बी/सी माली।
3. अंजू पुत्री श्री सूरज करण @ सूरजमल बी/सी माली।
4. नानू राम पुत्र श्री सूरज करण @ सूरजमल बी/सी माली। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 श्री सूरज करण @ सूरजमल की विधवा माता श्रीमती साम्या के माध्यम से।
5. श्री कल्याण पुत्र श्री बख्तावर बी/सी माली।
6. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री कल्याण बी/सी माली। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 7 तक ग्राम खोटिया तहसील शापुर जिला बझीलवाड़ा के निवासी हैं।
7. श्री संजय यादव पुत्र श्री राजेंद्र सिंह बी/सी यादव निवासी यादवा ट्रांसपोर्ट नगर, भीलवाड़ा (मालिक)।
8. श्री बजरंग लाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बी/सी शर्मा निवासी ग्राम व तहसील विजय नगर, जिला अजमेर (चालक)।

**----प्रत्यर्थी**

---

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी की ओर से | : | श्री जगदीश व्यास |
| प्रत्यर्थी की ओर से | : | आर.1 से 6 के लिए श्री सुभम मोदी और श्री उदित मोदी<br>आर.7 से 8 तक कोई भी उपस्थित नहीं। |

---

**माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी**

**आदेश**

**रिपोर्टेबल**

**01/05/2023**

1. यह अपील सिविल विविध केस संख्या 123/2000 (सी.एम.38) में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गुलाबपुरा, कैंप, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2001 से उत्पन्न हुई है। जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने दावेदारों को मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए केवल बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया है। ट्रिब्यूनल के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी बीमा कंपनी ने यह अपील दायर की है।

2. वर्तमान अपील में प्रश्न उठता है कि क्या मामले के तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोषी वाहन के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था?

3. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.09.1996 को समय लगभग 2.15 बजे। जब सूरज करण @ सूरज मल माली अपने मालिक की मिल में ड्यूटी पर जा रहा था और विवेकानन्द स्कूल के पास पहुंचा तो एक तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "कार्य") की धारा 140 और 166 के तहत मुआवजे के लिए एक आवेदन दायर किया। अपीलार्थी बीमा कंपनी ने एक विशिष्ट दलील के साथ लिखित बयान दायर किया कि ड्राइवर के पास एच.जी.वी. (भारी माल वाहन) चलाने का लाइसेंस था। केवल जबकि वह एक बस चला रहा था जो एक भारी यात्री वाहन था।

4. मालिक ने शामिल वाहन की बीमा पॉलिसी के अस्तित्व और बीमा कंपनी पर दायित्व तय करने का अनुरोध किया है। वहीं बीमा कंपनी ने दुर्घटना के तरीके, बस चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने से इनकार किया है और बस चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने की भी दलील दी है।

5. दलीलों के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण ने 5 मुद्दों को तय किया, लेकिन अपीलार्थी द्वारा केवल मुद्दा संख्या 3 का निर्धारण किया गया है, जो कि अपराधी वाहन के चालक द्वारा वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने के संबंध में है। विद्वान न्यायाधिकरण ने बस चालक के ड्राइविंग लाइसेंस पर विचार किया और कहा कि यह साबित नहीं होता है कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसा

मानते हुए, मालिक को दोषमुक्त करते हुए बीमा कंपनी को पंचाट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

6. हालाँकि बस के मालिक की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई गई थी लेकिन उनके अधिवक्ता मामले पर बहस के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुझे निम्नलिखित आधारों पर अपील पर निर्णय था:-

> "क्या दुर्घटना के समय अपराधी बस के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था?"

7. अपीलार्थी बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश व्यास ने तर्क दिया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 3 पर विचार किए बिना बीमाकर्ता को पंचाट का भुगतान करने के लिए दोषी ठहराते हुए गलती की है क्योंकि वाहन के मालिक ने पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन किया है। स्थिति; विद्वान न्यायाधिकरण ने राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 2.2 के साथ-साथ अधिनियम की धारा 3 पर विचार किए बिना, बीमा कंपनी के खिलाफ विवादित निर्णय पारित कर दिया है, इसलिए बीमा कंपनी को पंचाट के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर विचार न करके गलती की है कि अपराधी बस के चालक के पास भारी माल वाहन का लाइसेंस था, लेकिन वह एक यात्री बस चला रहा था, जिसके लिए चालक के पास या तो एच.पी.वी. (भारी यात्री वाहन) श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस या एच.जी.वी. के उनके मौजूदा लाइसेंस पर एच.पी.वी. प्राधिकार होना आवश्यक था। विद्वान न्यायाधिकरण को दोषी बस के मालिक के खिलाफ निर्णय पारित करना चाहिए था क्योंकि उसने ऐसे ड्राइवर को वाहन दिया था जो बस चलाने के लिए अधिकृत नहीं था। इन आधारों पर पंचाट पर पुनः विचार करने की प्रार्थना की गई है। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया है।

8. मैंने पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित निर्णय का अध्ययन किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. वर्तमान मामले में, अपराधी वाहन के चालक को 1994 के अधिनियम 54 द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधन से पहले ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था।

10. अधिनियम की धारा 10 गाड़ी चलाने के लाइसेंस के प्रपत्र और सामग्री से संबंधित है।

धारा 10 जैसा कि यह 1994 के संशोधन अधिनियम 54 के आधार पर वर्ष 1994 में किए गए संशोधन से पहले थी, यहां नीचे दी गई है:-

**10. वाहन चलाने के लाइसेंस का प्रपत्र और सामग्री-**

(1) प्रत्येक शिक्षार्थी लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, धारा 18 के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़कर, ऐसे प्रारूप में होंगे और इसमें ऐसी जानकारी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(2) एक शिक्षार्थी लाइसेंस या, जैसा भी मामला हो, ड्राइविंग लाइसेंस को धारक को निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक के मोटर वाहन चलाने के अधिकार के रूप में भी व्यक्त किया जाएगा, अर्थात:-

(क) बिना गियर वाली मोटरसाइकिल;
(ख) गियर वाली मोटरसाइकिल;
(ग) अमान्य गाड़ी;
(घ) हल्के मोटर वाहन;
(ङ) मध्यम माल वाहन;
(च) मध्यम यात्री मोटर वाहन;
(छ) भारी माल वाहन;
(ज) भारी यात्री मोटर वाहन;
(झ) रोडरोलर;
(ञ) एक निर्दिष्ट विवरण का मोटर वाहन।

11. वर्ष 1994 में किए गए संशोधन से पहले मौजूद पूर्व-संशोधित प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जिस वाहन के लिए लाइसेंस जारी किया जाता था उसका वर्ग या विवरण अन्य बातों के साथ-साथ हल्के मोटर वाहन, मध्यम माल वाहन, मध्यम यात्री मोटर वाहन, भारी माल वाहन, भारी यात्री मोटर वाहन और एक निर्दिष्ट विवरण के मोटर वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। परिवहन वाहन एक अलग वर्ग नहीं था, और यह धारा 10(1) (घ) से (ज) के तहत हो सकता है।

12. धारा 10 के पूर्व-संशोधित प्रावधान में धारा 10(2) (क) से (ञ) तक दस प्रकार के वाहन शामिल थे। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, मध्यम माल वाहन, मध्यम यात्री मोटर वाहन, भारी माल वाहन और भारी यात्री मोटर वाहन जैसी श्रेणियों को हटा दिया गया और इन चार प्रकार के वाहनों के लिए धारा 10(2)(ङ) में "परिवहन"

वाहन" के रूप में एक श्रेणी डाली गई। ताकि ड्राइवरों को उपरोक्त चार प्रकार के वाहनों के लिए बार-बार लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता न हो। 1994 के अधिनियम 54 द्वारा किए गए संशोधन के बाद धारा 10 का प्रावधान यहां दिया गया है:

**10. गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का प्रपत्र और सामग्री-** (1) प्रत्येक शिक्षार्थी लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, धारा 18 के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़कर, ऐसे प्रारूप में होंगे और इसमें ऐसी जानकारी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(2) एक शिक्षार्थी लाइसेंस या, जैसा भी मामला हो, ड्राइविंग लाइसेंस को धारक को निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक के मोटर वाहन चलाने के अधिकार के रूप में भी व्यक्त किया जाएगा, अर्थात:-

(क) बिना गियर वाली मोटरसाइकिल;
(ख) गियर वाली मोटरसाइकिल;
(ग) अमान्य गाड़ी;
(घ) हल्के मोटर वाहन;
(ङ) परिवहन वाहन;
(च) मध्यम यात्री मोटर वाहन;
(छ) भारी माल वाहन;
(ज) भारी यात्री मोटर वाहन;
(झ) रोडरोलर;
(ञ) एक निर्दिष्ट विवरण का मोटर वाहन।

13. मैंने साक्ष्य और दलीलें पढ़ ली हैं। अपीलार्थी बीमा कंपनी के प्रभागीय प्रबंधक, एनएडब्ल्यू1 ओमप्रकाश मुथा के बयान के आधार पर, बीमाकर्ता यह साबित करने में सक्षम है कि दुर्घटना के समय, अपराधी वाहन के चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था जो उसे केवल एचजीवी श्रेणी का वाहन चलाने के लिए अधिकृत करता था जबकि, सम्मिलित वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र (प्रदर्श-4) के अनुसार, वह एक भारी यात्री वाहन चला रहा था, जिसके लिए उसके पास एच.पी.वी. श्रेणी का डी.एल. की श्रेणी या एच.पी.वी. का प्राधिकार होना अनिवार्य था। जो अधिनियम की पूर्व-संशोधित धारा 10 के अनुसार अपेक्षित है। इससे साबित होता है कि बीमाधारक लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित

सावधानी करने में विफल रहा था।

14. दुर्घटना के समय चालक भारी यात्री वाहन चलाने के लिए योग्य या अधिकृत नहीं था, इस प्रकार, मैं मानता हूं कि बीमा कंपनी मालिक की ओर से बीमा पॉलिसी के उल्लंघन को स्थापित करने में सफल रही है। प्रत्यर्थी बस मालिक या ड्राइवर बीमाकर्ता द्वारा दिए गए सबूतों का खंडन करने में विफल रहे।

15. वर्तमान मामले में, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक सूरज करण @ सूरज मल माली तीसरा पक्ष था।

16. तीसरे पक्ष के जोखिम के मामले में, ***"नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम" स्वर्ण सिंह एवं अन्य (2004) 03 एससीसी 297***" के निर्णय के अनुसार बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष को देय मुआवजे की राशि की क्षतिपूर्ति करनी थी और बीमा कंपनी बीमाधारक से इसकी वसूली कर सकती है। उपरोक्त मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा "भुगतान और वसूली" के सिद्धांत पर विचार किया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ड्राइवर की अयोग्यता या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस के कारण पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के मामले में बीमा कंपनी की देनदारी की जांच की थी। बीमाकर्ता के संविदात्मक दायित्व के साथ-साथ तीसरे पक्ष के दावों जैसे वैधानिक दायित्व पर विस्तार से विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए कि कैसे और किन परिस्थितियों में, "भुगतान करें और पुनर्प्राप्त करें" का आदेश दिया जा सकता है।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया:-

> 110. इन याचिकाओं में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है:
>
> (i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अध्याय XI, तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ वाहनों का अनिवार्य बीमा प्रदान करना, मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के माध्यम से राहत देने के लिए एक सामाजिक कल्याण कानून है। सभी वाहनों के अनिवार्य बीमा कवरेज के प्रावधान इस सर्वोपरि उद्देश्य के साथ हैं और अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि उक्त उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके।
>
> (ii) एक बीमाकर्ता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-क या धारा

166 के तहत दायर दावा याचिका में, अन्य बातों के अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 149(2)(क)(ii) के संदर्भ में बचाव करने का हकदार है।

(iii) पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन जैसे ड्राइवर की अयोग्यता या ड्राइवर का अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि धारा 149 की उपधारा (2)(क)(ii) में निहित है, को बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए बीमाधारक द्वारा किया गया अपराध साबित करना होगा। केवल अनुपस्थिति, नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या प्रासंगिक समय पर ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की अयोग्यता, अपने आप में बीमाकर्ता या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं है। बीमाधारक के प्रति अपनी देनदारी से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमाधारक लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर या ऐसे व्यक्ति द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी करने में विफल रहा था। प्रासंगिक समय पर गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य नहीं था।

(iv) हालाँकि, बीमा कंपनियों को अपनी देनदारी से बचने के लिए न केवल उक्त कार्यवाही में उठाए गए उपलब्ध बचाव को स्थापित करना चाहिए, बल्कि वाहन के मालिक की ओर से "उल्लंघन" को भी स्थापित करना चाहिए; इसलिए सबूत का बोझ उन पर होगा,

(v) अदालत इस बारे में कोई मानदंड नहीं तय कर सकती है कि उक्त बोझ का निर्वहन कैसे किया जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(vi) यहां तक कि जहां बीमाकर्ता प्रासंगिक अवधि के दौरान ड्राइवर द्वारा वैध लाइसेंस रखने या गाड़ी चलाने की योग्यता के संबंध में पॉलिसी की शर्तों के संबंध में बीमाधारक की ओर से उल्लंघन साबित करने में सक्षम है, बीमाकर्ता को बीमाधारक के प्रति उत्तरदायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।, जब तक कि उक्त उल्लंघन या ड्राइविंग लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन इतना मौलिक न हो कि दुर्घटना के कारण में योगदान देता हो। पॉलिसी शर्तों की व्याख्या में न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 149(2) के तहत बीमाकर्ता को

बचाव की अनुमति देने के लिए "मुख्य उद्देश्य के नियम" और "मौलिक उल्लंघन" की अवधारणा को लागू करेंगे।

(vii) यह प्रश्न, कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस (नकली या अन्यथा), कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या नहीं, हर मामले में यह निर्धारित करना होगा।

(viii) यदि दुर्घटना के समय वाहन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास लर्नर लाइसेंस है, तो बीमा कंपनियां डिक्री को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

(ix) धारा 165 के साथ पठित धारा 168 के तहत गठित दावा न्यायाधिकरण को मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली मृत्यु या शारीरिक चोट या तीसरे पक्ष की संपत्ति की क्षति से जुड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में सभी दावों पर निर्णय करने का अधिकार है। ट्रिब्यूनल की उक्त शक्ति एक तरफ दावेदार या दावाकर्ताओं और दूसरी तरफ बीमाधारक, बीमाकर्ता और ड्राइवर के बीच दावों पर निर्णय लेने तक सीमित नहीं है। मुआवजे के दावे पर निर्णय लेने और बीमाकर्ता के लिए बचाव या सुरक्षा की उपलब्धता तय करने के दौरान, ट्रिब्यूनल के पास बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच विवादों को तय करने की शक्ति और क्षेत्राधिकार होता है। दावेदारों द्वारा मुआवजे के दावे के निर्णय के दौरान बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच दावों और विवादों पर दिया गया निर्णय और उस पर दिया गया पंचाट उसी तरीके से लागू और निष्पादन योग्य है जैसा कि प्रवर्तन दावेदारों के पक्ष में पंचाट का और निष्पादन अधिनियम की धारा 174 में किया गया है।

(x) जहां अधिनियम के तहत दावे के निर्णय पर ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बीमाकर्ता ने उपधारा (7) के साथ पठित धारा 149(2) के प्रावधानों के अनुसार अपना बचाव संतोषजनक ढंग से साबित कर दिया है, जैसा कि उपरोक्त न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या की गई है, ट्रिब्यूनल निर्देश दे सकता है कि बीमाकर्ता बीमाधारक द्वारा मुआवजे और अन्य रकम की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है जिसे ट्रिब्यूनल के निर्णय के तहत तीसरे पक्ष को

भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया है। ट्रिब्यूनल द्वारा दावे का ऐसा निर्धारण प्रवर्तनीय होगा और बीमाधारक से बीमाकर्ता को देय धनराशि, ट्रिब्यूनल द्वारा कलेक्टर को जारी प्रमाण पत्र पर अधिनियम की धारा 174 के तहत भू-राजस्व के बकाया के समान वसूली योग्य होगी। भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा, जब अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (3) के अनुसार बीमाधारक ट्रिब्यूनल द्वारा पंचाट की घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर बीमाकर्ता के पक्ष में दी गई राशि जमा करने में विफल रहता है।

(xi) "उप-धारा (4) में दिए गए प्रावधान और उप-धारा (5) के तहत प्रावधान, जिसका उद्देश्य उसमें उल्लिखित निर्दिष्ट आकस्मिकताओं को कवर करना है ताकि बीमाकर्ता को अपनी ओर से बीमा अनुबंध के तहत बीमाधारक की ओर से भुगतान की गई राशि की वसूली करने में सक्षम बनाया जा सके और बीमाधारक को ट्रिब्यूनल का सहारा लिया जा सकता है और उन मामलों में बीमाधारक के खिलाफ बीमाकर्ता के दावों और बचावों को नियमित अदालत के समक्ष उपचार के लिए भेजा जा सकता है, जहां दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पीड़ितों के दावों के न्यायनिर्णयन, उनके दावों के निर्णय में देरी हो सकती है।

18. स्वर्ण सिंह मामले में निर्णय के अनुसार, यह साबित करने का दायित्व हमेशा बीमा कंपनी पर होता है कि ड्राइवर के पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन हुआ था। जहां ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन है, तीसरे पक्ष के जोखिम के मामले में "भुगतान करें और वसूली" का आदेश दिया जा सकता है।

19. परिणामस्वरूप, उपरोक्त के मद्देनजर, निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन होने पर, बीमाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

20. जहां तक विद्वान न्यायाधिकरण के निर्णय का प्रश्न है, मेरा विचार है कि, न्यायाधिकरण को वाहन के मालिक को दोषमुक्त नहीं करना चाहिए था क्योंकि वह पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन का दोषी था। चूंकि, शामिल वाहन का बीमा किया गया था, इसलिए

वाहन मालिक और बीमा कंपनी दोनों मुआवजे का भुगतान करने के लिए संयुक्त और कई दायित्वों के लिए उत्तरदायी थे।

21. जहां तक वाहन के मालिक से राशि की वसूली की बात है, बीमा ***कंपनी "ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नंजप्पन और अन्य (2004) 13 एससीसी 224***' के निर्णय के अनुसार वसूली करेगी, जहां इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

> "...कि बीमाधारक से इसे वसूलने के उद्देश्य से, बीमाकर्ता को मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है जैसे कि बीमाकर्ता और मालिक के बीच विवाद ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्धारण का विषय था और मुद्दा मालिक के खिलाफ और बीमाकर्ता के पक्ष में तय किया गया है।

22. परिणामस्वरूप, केवल बीमा कंपनी को मुआवजा देने का निर्देश देने वाले आक्षेपित निर्णय संशोधित होने योग्य है।

23. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और दिनांक 16.07.2001 के निर्णय को इस हद तक संशोधित किया गया है कि अपीलार्थी बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा देगी और वाहन के मालिक से इसकी वसूली करेगी। कोई लागत नहीं।

24. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

**(राजेन्द्र प्रकाश सोनी), न्यायमूर्ति**

1-nitin/-

**टिप्पणी:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।